



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 10, 2005/पौष 20, 1926

No. 10]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 10, 2005/PAUSA 20, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण

(सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2005

सं. 1/2005-एएआर

सा.का.नि. 12(अ).— अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर), सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 28ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 23ज और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 96ज द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है उक्त अधिनियमों के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों से अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर) प्रक्रिया विनियम, 2005 ["एएआरयूएल (सीईएसटी) प्रक्रिया विनियम"] है ।

(2) ये 26 जनवरी, 2005 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं— इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अग्रिम विनिर्णय" से, यथास्थिति, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 28ड के खंड (ख) या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 23क के खंड (ख) या वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (सेवा कर उपबंधों के रूप में इसमें निर्दिष्ट उक्त अधिनियम के

अध्याय 5 और अध्याय 5क) के अध्याय 5क में धारा 96क के खंड (क) में यथा परिभाषित अग्रिम विनिर्णय अभिप्रेत है ;

(ख) “आवेदक” से, यथास्थिति, उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 28ड के खंड(ग) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क के खंड (ग) या सेवा कर उपबंधों की धारा 96क के खंड (ख) में यथा परिभाषित कोई आवेदक अभिप्रेत है ;

(ग) “आवेदन” से, यथास्थिति, उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 28ज की उपधारा (1) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 23ग की उपधारा (1) या सेवा कर उपबंधों की धारा 96ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन अभिप्रेत है ;

(घ) “प्राधिकृत प्रतिनिधि” से,-

(i) आवेदक के संबंध में, यथास्थिति, उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 146क की उपधारा (2) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35थ की उपधारा (2) में यथा परिभाषित या सेवा कर उपबंधों की धारा 96घ की उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्राधिकृत प्रतिनिधि अभिप्रेत है ;

(ii) आयुक्त के संबंध में, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है-

(क) जो आयुक्त द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ; या

(ख) जिसे प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में आयुक्त के लिए उपसंज्ञात होने, अभिवाक् करने और कार्य करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है या जिसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है ;

(ड) “प्राधिकरण” से उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 28च के अधीन गठित और उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क के खंड (ड) और सेवा कर उपबंधों की धारा 96क के खंड (घ) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(च) “अध्यक्ष” से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(छ) आवेदन के संबंध में “आयुक्त” से अभिप्रेत है -

(i) आवेदन में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त ; या

(ii) आवेदन की बाबत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित आयुक्त ;

(ज) “सदस्य” से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी हैं ;

(झ) “अर्जी” से अर्न्तवर्ती, आनुषंगिक या प्रासंगिक प्रकृति की कोई अर्जी या लंबित और निपटाए गए आवेदन में फाईल किया गया अभ्यावेदन अभिप्रेत है ;

(ञ) “नियम” से यथास्थिति सीमा-शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियम, 2002 या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियम, 2002 या सेवा कर (अग्रिम विनिर्णय) नियम, 2003 अभिप्रेत है ;

(ट) “सचिव” से प्राधिकरण द्वारा सचिव के रूप में पदाभिहित सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस प्रकार पदाभिहित सीमा-शुल्क का या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त भी हैं ;

(ठ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु, यथास्थिति, उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम या उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या सेवा कर उपबंधों में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ हैं जो उस अधिनियमिति में उनके हैं ।

3. प्राधिकरण की भाषा- (1) प्राधिकरण की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी ।

(2) जहां कोई दस्तावेज हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में है वहां मूल दस्तावेज के साथ सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित उसका हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद फाईल किया जाएगा ।

4. प्राधिकरण की शक्तियां - (1) प्राधिकरण को सभी आवेदनों और अर्जियों की सुनवाई और उनको अवधारित करने की शक्ति होगी ।

(2) यदि प्राधिकरण के किसी आदेश/अग्रिम विनिर्णय को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो प्राधिकरण या तो स्वप्रेरणा से या आवेदक या आयुक्त द्वारा की गई अर्जी पर कठिनाई की सूचना होने के तीन मास की अवधि के भीतर ऐसी कठिनाई को समुचित

आदेश द्वारा दूर कर सकेगा, और मामले की परिस्थितियों में जैसा वह न्याय संगत और आवश्यक समझता है ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा ।

(3) प्राधिकरण पर्याप्त कारण से अपने आदेश/अग्रिम विनिर्णय के सुनाने के पूर्व किसी मामले की नए सिरे से सुनवाई कर सकेगा ।

(4) प्राधिकरण किसी समुचित मामले में निम्नलिखित के लिए निदेश दे सकेगा-

- (i) किन्हीं अभिलेखों की परीक्षा और रिपोर्ट को प्रस्तुत करना ;
- (ii) किसी माल या सेवाओं की कोई तकनीकी, वैज्ञानिक या बाजार जांच करना और रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना और विशेषज्ञों से रिपोर्टों की मांग भी कर सकेगा और ऐसे और अन्वेषण के आदेश कर सकेगा जो आवेदन के प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक हो ।

(5) प्राधिकरण को निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

- (i) प्रकटीकरण और निरीक्षण ;
- (ii) किसी व्यक्ति की उपस्थिति प्रवर्तित करना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना ;
- (iii) कमीशन निकालना ; और
- (iv) लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को पेश करने के लिए विवश करना ।

5. **सचिव की शक्तियां और कृत्य :-** (1) सचिव प्राधिकरण के कार्यालय का संपूर्ण प्रभारी होगा और अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

(2) सचिव-

(क) की अभिरक्षा में प्राधिकरण के अभिलेख और प्राधिकारिक मुद्रा होगी ;

(ख) प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए गए सभी आवेदन और अर्जियां प्राप्त करेगा ;

(ग) आवेदन और अर्जियों की संवीक्षा करेगा और आवेदन/अर्जी में लोप और त्रुटियां बताएगा और सचिव द्वारा दिए गए समय के भीतर लोपों को ठीक करने या त्रुटियों को दूर करने के लिए आवेदक/अर्जीदार से अपेक्षा करेगा और अननुपालन की दशा में समुचित आदेशों के लिए प्राधिकरण के समक्ष ऐसे आवेदन/अर्जी को रखेगा ;

(घ) मामला यदि कोई हो तो अभिलेखों को पारेषित करने के लिए आयुक्त को उसके संलग्नकों के साथ आवेदन की प्रति और आवेदन पर उसकी टीका-टिप्पणियों को प्रस्थापित करने के लिए अग्रेषित करेगा ;

(ङ) यथास्थिति, उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 28झ की उपधारा (2) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 23घ की उपधारा (2) या सेवा कर उपबंधों की धारा 96घ की उपधारा (2) के अधीन समुचित आदेशों के लिए प्राधिकरण के समक्ष सभी आवेदनों को रखेगा ;

(च) ऐसी सूचनाओं और अन्य आदेशिकाओं को जारी करेगा जो प्राधिकरण द्वारा आदेशित की जाएं ;

(छ) आवेदन/अर्जी के पक्षकारों की सूचना और अन्य आदेशिकाओं की तामिल सत्यापित करेगा और त्रुटिपूर्ण तामिल की दशा में अध्यक्ष के आवश्यक आदेश अभिप्राप्त करेगा ;

(ज) प्राधिकरण के आदेशों पर किसी व्यक्ति की अभिरक्षा से अभिलेखों की मांग करेगा ;

(झ) उस व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से वे मांगे गए थे, को मूल अभिलेखों को वापस करेगा ;

(ञ) प्राधिकरण के अभिलेखों का निरीक्षण अनुज्ञात करेगा ;

(ट) उसके अनुदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण के अभिलेखों का कोई संशोधन कार्यान्वित करेगा ;

(ठ) आदेशों/अग्रिम विनिर्णयों और प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में फाइल किए गए दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां, आवेदन/अर्जी के पक्षकारों को प्रदत्त करेगा ;

(ड) आवेदन के निपटान की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक आवेदन/अर्जी और अन्य सामाग्रियों के अभिलेख को सुरक्षित रखेगा और प्राधिकरण द्वारा जब तक कि अन्यथा निदेशित न किया जाए उसके पश्चात् उसे उसकी छटनी/नष्ट करने के लिए सुरक्षित रखेगा ; और

(ढ) ऐसे किसी अन्य कृत्य का पालन करेगा जो विशेष या साधारण आदेश द्वारा प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किया जाए ।

6. सूचनाओं, आदि को हस्ताक्षरित किया जाना- (1) प्राधिकरण की ओर से जारी की जाने वाली प्रत्येक अध्यक्ष, निदेश, पत्र, प्राधिकार या सूचना सचिव द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी ।

(2) उप विनियम (1) की कोई बात ऐसे किसी निदेश पर लागू नहीं होगी, जिसे प्राधिकरण सुनवाई के अनुक्रम में उपस्थित किसी आवेदक या किसी आयुक्त या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को जारी करे ।

7. सूचनाओं आदि की तामील का ढंग- (1) ऐसी प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज, जो प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना में किसी व्यक्ति पर तामील किए जाने या परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित है, इसके अधीन विनिर्दिष्ट रीति में तामील या परिदत्त किए जाएंगे ।

(2) सूचना या दस्तावेज की तामील व्यक्तिगत रूप से परिदत्त करके या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या कूरियर सेवा द्वारा या दस्तावेजों जिसके अन्तर्गत ई-मेल/फैक्स भी है, के पारेषण के किसी अन्य साधनों द्वारा की जाएगी ।

(3) आवेदन/अर्जी के पक्षकारों पर तामील की जाने के लिए अपेक्षित सूचनाएं या दस्तावेज यदि आवेदन/अर्जी उपदर्शित पते पर और आयुक्त की दशा में आयुक्त के कार्यालय में परिदत्त किए जाते हैं तो तामील किया जाना समझा जाएगा ।

8. आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया-(1) प्राधिकरण के समक्ष फाइल किया गया प्रत्येक आवेदन विहित प्ररूप में होगा, अर्थात् यथास्थिति सीमा शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियम, 2002 के प्ररूप-एएआर(सी.शु.) या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियम, 2002 के प्ररूप-एएआर(के.उ.शु.) या सेवा कर (अग्रिम विनिर्णय) नियम, 2003 के प्ररूप -एएआर(से.क.) ।

(2) आवेदन चार प्रतियों में फाइल किया जाएगा और उसे स्वयं आवेदक द्वारा या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सचिव को या सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और सचिव के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या कूरियर सेवा द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा दो हजार पांच सौ भारतीय रूपए की फीस सहित भेजा जाएगा, जो “अग्रिम विनिर्णय (सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर)” के पक्ष में नई दिल्ली में संदेय एक मांग देय ड्राफ्ट के रूप में होगी ।

(3) अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन कार्य दिवस को 10.00 बजे पूर्वाह्न और 1.00 बजे अपराह्न के बीच और 2.00 बजे अपराह्न और 5.00 बजे अपराह्न के बीच प्राप्त किए जाएंगे ।

(4) प्रत्येक आवेदन, इसका सत्यापन, इसके साथ लगे उपाबंध, विवरण तथा समर्थकारी दस्तावेज उस रीति में हस्ताक्षरित किए जाएंगे, जो नियमों में उपवर्णित है ।

(5) आवेदन के साथ यह साक्ष्य लगा होगा कि वह व्यक्ति जिसने आवेदन, सत्यापन और अन्य दस्तावेजों को हस्ताक्षरित किया है नियमों के अधीन हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत/साक्ष्य है ।

(6) प्रत्येक आवेदन इसका सत्यापन और इसके साथ लगे उपाबंध, विवरण तथा दस्तावेज ए-4 आकार के कागज पर होंगे और 5 सेंटीमीटर के बायें हाशिया को छोड़ते हुए और दोहरी रेखा स्थान में पृष्ठ के केवल एक तरफ स्वच्छ और पठनीय रूप में लिखा, टाईप या मुद्रित होना चाहिए ।

(7) उप विनियम (1) के अधीन किसी आवेदन को उस तारीख को फाईल किया गया समझा जाएगा जिसको उसे प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त किया जाता है ।

(8) यदि आवेदक का भारत में आधार नहीं है तो वह अन्य बातों के साथ-साथ आवेदन के पृथक उपाबंध में निम्नलिखित उपदर्शित करेगा-

(क) विदेश में उसका डाक और ई-मेल पता ;

(ख) उसकी ओर से कार्य करने और प्राधिकरण द्वारा भेजी गई सूचनाएं या अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत भारत में उसका प्रतिनिधि यदि कोई हो, का नाम और पता जिसके अन्तर्गत ई-मेल पता भी है ।

9. आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया- (1) आवेदन प्राप्त करने वाला अधिकारी उसकी प्राप्ति की तारीख और समय के साथ उस पर अपने अद्याक्षर करेगा और प्राधिकरण की स्टॉम्प लगाएगा और उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति भी करेगा और वह उस प्रयोजन के लिए रखे गए दैनिक फाइल करने के रजिस्टर में आवेदन की विशिष्टियों की भी प्रविष्टि करेगा ।

(2) आवेदन की किसी कमी/त्रुटि के लिए उस प्रयोजन के लिए सचिव द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी और आवेदन और उसके उपाबंधों में किसी कमी/त्रुटि का पता लगने पर शीघ्रता से आवेदक को संसूचित किया जाएगा ।

(3) आवेदन से सचिव द्वारा दिए गए समय के भीतर कमी/त्रुटि ठीक करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसा आवेदन उस तारीख को प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब वह, यथास्थिति,

उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 28झ की उपधारा (6) या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23घ की उपधारा (6) या सेवा कर उपबंधों की धारा 96घ की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए ऐसी कमी/त्रुटि के दूर किए जाने के पश्चात् पुनः प्रस्तुत किया जाता है ।

(4) प्राधिकरण के सचिवालय में किसी त्रुटि या कमी रहित आवेदन की प्राप्ति की तारीख उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28ज की उपधारा (4) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 23ग की उपधारा (4) या सेवा कर उपबंधों की 96ग की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए आवेदन की तारीख समझी जाएगी ।

(5) जब कोई आवेदन किसी त्रुटि/कमी से मुक्त है “परीक्षित और रजिस्ट्रीकृत” पृष्ठांकन उस पर किया जाएगा और उसको क्रम संख्यांक आवंटित किया जाएगा ।

(6) यदि उप विनियम (3) के अधीन दिए गए समय के भीतर त्रुटि/कमी दूर या ठीक नहीं की जाती है तो आवेदन समुचित आदेशों के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा ।

(7) उप विनियम (5) के अधीन किसी आवेदन के क्रम संख्यांक के आवंटन पर, आवेदन की एक प्रति सुसंगत अभिलेखों सहित टीका-टिप्पणियों, यदि कोई हो, भेजने के लिए संबद्ध सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को अग्रेषित की जाएगी ।

(8) उप विनियम (7) के अधीन संबद्ध आयुक्त से सुसंगत अभिलेखों/टीका-टिप्पणियों की प्राप्ति पर या दो सप्ताह या ऐसी और अवधि जो प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात की जाए की समाप्ति के पश्चात् आवेदन, यथास्थिति, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28झ की उपधारा (2) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 23घ की उपधारा (2) या सेवा कर उपबंधों की धारा 96घ की उपधारा (2) के निबंधनों के अनुसार आदेश पारित करने के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा ।

(9) यदि जहां प्राधिकरण समझता है कि आवेदन प्रथम दृष्ट्या खारिज किए जाने के लिए दायी है, आवेदक को एक सूचना जारी की जाएगी जिसके साथ उसके कारण के साथ संबद्ध आयुक्त की टीका-टिप्पणी यदि कोई, हो उपदर्शित किए जाएंगे जिसमें आवेदन को स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर दिया जाएगा और सूचना की एक प्रति संबद्ध आयुक्त को पृष्ठांकित की जाएगी ।

(10) सुनवाई के लिए नियत तारीख या ऐसी अन्य तारीख को, जिसको मामला स्थगित किया जाता है प्राधिकरण, यथास्थिति, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28झ की उपधारा (2) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 23घ की उपधारा (2) या सेवा कर उपबंधों की धारा 96घ की उपधारा (2) के अधीन आवेदन को या तो अनुज्ञात करते हुए या खारिज करते हुए

कोई आदेश पारित कर सकेगा और प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की एक प्रति आवेदन और संबद्ध आयुक्त को भेजी जाएगी।

(11) जहाँ आवेदन अनुज्ञात किया जाता है वहाँ कानूनी उपबंधों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करते हुए कि अग्रिम विनिर्णय के सुनाने के पूर्व यदि वह ऐसा चाहता है तो उसका सुने जाने का अधिकार है, आवेदक को भेजे गए आदेश की प्रति के साथ संबद्ध आयुक्त की टीका-टिप्पणियाँ और अतिरिक्त सामाग्री, यदि कोई हो, लगी होगी और आवेदक का जवाब आदेश की प्रति की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर प्राधिकरण के पास पहुँच जाना चाहिए।

(12) आवेदन की सुनवाई सामान्यतः कार्य दिवस को 11.00 बजे पूर्वाह्न और 5.00 बजे अपराह्न के बीच प्राधिकरण के न्यायालय कक्ष या प्राधिकरण द्वारा नियत आनुकूलिक स्थान में आयोजित की जाएगी।

(13) आवेदक से व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध की अनुपस्थिति में अग्रिम विनिर्णय संबद्ध आयुक्त या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि सुनवाई की तारीख को उपस्थित हो, की सुनवाई के पश्चात् और प्राधिकरण के पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सुना दिया जाएगा।

(14) जहाँ प्राधिकरण अग्रिम विनिर्णय या ऐसा अन्य आदेश, जो प्राधिकरण ठीक समझे पर विचार करने के लिए आवेदन को आरक्षित रखता है तो आवेदक और संबद्ध आयुक्त की सूचना के अधीन रहते हुए खुले न्यायालय में सुना दिया जाएगा और अग्रिम विनिर्णय/आदेश की प्रति आवेदन के पक्षकारों पर आरक्षित होगी।

10. बोर्ड द्वारा आयुक्त का पदामिहित किया जाना- जहाँ किसी आवेदन में आवेदक द्वारा कोई आयुक्त विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है वहाँ आवेदन की एक प्रति और उसके संलग्नक प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क अध्यक्ष को अग्रेषित की जाएगी, जिसमें आवेदन के प्रयोजनों के लिए आयुक्त ऐसी अवधि के भीतर जो प्राधिकरण द्वारा नियत की जाए, कोई आयुक्त पदामिहित करने के लिए उससे मांग की जाएगी। जिसके न हो सकने पर आवेदन पर आयुक्त की अनुपस्थिति में आगे कार्यवाही की जाएगी।

11. अर्जी के रूप में अतिरिक्त तथ्य-(1) प्राधिकरण अपने विवेक से या तो स्वप्रेरणा से या आवेदन के किसी पक्षकार द्वारा इस प्रभाव के लिए की गई किसी अर्जी पर आवेदक या आयुक्त से उसके अग्रिम विनिर्णय सुनाने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए ऐसे अतिरिक्त तथ्य जो आवश्यक हो को अनुज्ञात कर सकेगा या अपेक्षा कर सकेगा।

(2) अर्जीदार द्वारा रिकार्ड पर लाए जाने के लिए चाहे गए अतिरिक्त तथ्य, सम्यक् रूप से सत्यापित आवश्यक दस्तावेजों, यदि कोई हो, द्वारा समर्थित होंगे।

12. ऐसे प्रश्न जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं हैं- (1) आवेदक, प्राधिकरण की इजाजत के बिना आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न से भिन्न किसी प्रश्न के संबंध में प्रार्थना नहीं करेगा या उसकी सुनवाई नहीं होगी, किंतु आवेदन में उपवर्णित प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय के सुनाए जाने में प्राधिकरण अपने विवेक से ऐसे अन्य पहलुओं पर विचार करेगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय के सुनाने के लिए आवश्यक हो ।

(2) आवेदक द्वारा दी गई अर्जी पर प्राधिकरण समुचित मामलों में किसी प्रश्न का संशोधन अनुज्ञात कर सकेगा ।

13. प्राधिकार का फाइल किया जाना- (1) आवेदक/आयुक्त के लिए उपसंजात होने वाला प्राधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई के प्रारंभ होने के पूर्व एक दस्तावेज फाइल करेगा जिसमें आयुक्त की ओर से उपसंजात होने के लिए उसे प्राधिकृत किया गया हो ।

(2) आवेदक/आयुक्त की ओर से उपसंजात होने वाला प्रत्येक प्राधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई के प्रारंभ के पूर्व उसके कार्यालय के पते पर सचिव को अधिसूचित करेगा ।

(3) प्राधिकृत प्रतिनिधि के किसी परिवर्तन को सचिव तथा आवेदन के अन्य पक्षकार को सम्बद्ध पक्षकार द्वारा संसूचित किया जाएगा ।

(4) आवेदक या संबद्ध आयुक्त या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से भिन्न किसी व्यक्ति को स्वयं प्राधिकरण की विशेष इजाजत के सिवाय नहीं सुना जाएगा ।

14. आवेदक की मृत्यु, आदि के पश्चात् कार्यवाही का जारी रहना- जहां आवेदक जो एक व्यक्ति है, की मृत्यु हो जाती है, या जो एक कंपनी या व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं उसका परिसमापन या विघटन अथवा विभाजन या सम्मेलन हो जाता है या किसी अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकार में आ जाती है अथवा अन्यथा समाप्त हो जाती है तो आवेदन का उपशमन नहीं होगा और जहां प्राधिकरण यह समझता है कि परिस्थितियां इसे न्यायोचित ठहराती हैं वहां इस निमित्त आवेदन करने पर कार्यवाहियों को आवेदक के, यथास्थिति, निष्पादक, प्रशासक, परिसमापक, रिसीवर या समनुदेशिनी या अन्य विधिक प्रतिनिधि द्वारा जारी रखा जा सकेगा ।

15. आवेदन की सुनवाई-(1) प्राधिकरण नियत तारीख को या किसी अन्य दिन को जिसको मामला स्थगित किया जाता है ऐसे मामलों में आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की सुनवाई करेगा जिसमें आवेदन को नामंजूर करने का प्रस्ताव है या आवेदक भी सुने जाने का अवसर चाहता है ; प्राधिकरण आयुक्त या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की भी सुनवाई कर सकता है यदि वह अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाने के पूर्व यह आवश्यक समझता है ।

(2) समुचित मामले में प्राधिकरण, किसी व्यक्ति से अभिसाक्ष्य देने या ऐसी सामाग्री/दस्तावेज प्रदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा जिसे वह विनिश्चय करने के लिए आवश्यक समझे ।

(3) प्राधिकरण किसी समुचित मामले में जहां विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न उद्भूत होता है, वहां केन्द्रीय सरकार के विधि-अधिकारी जिसके अन्तर्गत उस मामले में प्राधिकरण की सहायता करने के लिए महान्यायवादी और महासालिसिटर भी हैं, को सूचना जारी कर सकेगा ।

(4) आवेदन में प्राधिकरण की सहायता करने के लिए न्याय-मित्र के रूप में किसी अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए भी प्राधिकरण स्वतंत्र होगा ।

(5) प्राधिकरण ऐसी शर्तों पर जो मामले की परिस्थितियों के लिए अपेक्षित हों आवेदन की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा ।

16. आवेदन की एक-पक्षीय सुनवाई- जहां नियत तारीख को या किसी अन्य दिन को जिसको मामला स्थगित किया जाता है आवेदक या आयुक्त सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर भी स्वयं या प्राधिकृति प्रतिनिधि के माध्यम से उपसंजात नहीं होता है वहां प्राधिकरण आवेदन को गुणागुण के आधार पर एक पक्षीय रूप में निपटा सकेगा:

परंतु यह कि जहां आवेदन इस विनियम के अधीन निपटाया गया है और यथास्थिति, आवेदक या आयुक्त आदेश/अग्रिम विनिर्णय की प्रति की प्राप्ति के सात दिन के भीतर आवेदन करता है और प्राधिकरण को यह समाधान हो जाता है कि जब आवेदन की सुनवाई के लिए उसे बुलाया गया था तब उपसंजात न होने के लिए पर्याप्त कारण था तो प्राधिकरण विपक्ष को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देकर एक-पक्षीय आदेश/अग्रिम विनिर्णय को अपास्त करने का आदेश दे सकेगा और आवेदन को नए सिरे से सुनवाई के लिए पुनः स्थापित कर सकेगा ।

17. आवेदन का वापस लिया जाना- आवेदक ऐसे आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर और उसके पश्चात् केवल प्राधिकरण की इजाजत से अपने आवेदन को वापस ले सकेगा ।

18. आदेश/अग्रिम विनिर्णय का उपांतरण- प्राधिकरण स्वप्रेरणा से या आवेदक या आयुक्त द्वारा अर्जी दिए जाने पर किंतु अग्रिम विनिर्णय के सुनाने से पूर्व या अग्रिम विनिर्णय को प्रभावी किए जाने से पूर्व, यह समाधान हो जाने पर कि आदेश/अग्रिम विनिर्णय विधि या तथ्य की भूल से सुनाया गया था, आवेदक और आयुक्त को सुनवाई का उचित अवसर अनुज्ञात करने के पश्चात् ऐसे आदेश/अग्रिम विनिर्णय को इस प्रकार उपांतरित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे ।

19. भूलों की परिशुद्धि- (1) प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी भूल की परिशुद्धि के लिए उसके द्वारा सुनाए गए किसी अग्रिम विनिर्णय का, ऐसे विनिर्णय को प्रभावी किए जाने से पूर्व संशोधन कर सकेगा ।

(2) ऐसा संशोधन स्वप्रेरणा से किया जा सकेगा या तब किया जा सकेगा जब आवेदक या आयुक्त द्वारा भूल प्राधिकरण की जानकारी में लाई जाती है किंतु ऐसा केवल आवेदक और आयुक्त को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा ।

20. अभिलेखों का संशोधन- यदि कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर प्राधिकरण की जानकारी में यह लाया जाता है कि अभिलेखों में कोई तथ्य संबंधी या तात्त्विक गलती है तो प्राधिकरण आवेदक और आयुक्त को सुने जाने के पश्चात् अभिलेखों का संशोधन अनुज्ञात कर सकेगा ।

21. प्रमाणित प्रतियां का प्रदाय किया जाना- सचिव, आवेदक या आयुक्त को, लिखित अनुरोध पर दस्तावेजों, आदेशों या अग्रिम विनिर्णयों की प्रमाणित प्रतियां मंजूर कर सकेगा ।

22. अभिलेखों का निरीक्षण- (1) आवेदक या आयुक्त या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि केवल उन दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जिनका प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में आश्रय लिया गया है, सचिव को लिखित अनुरोध करने पर आवेदन/अर्जी के अभिलेखों के निरीक्षण के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) निरीक्षण केवल प्राधिकरण के किसी अधिकारी की उपस्थिति में ही अनुज्ञात किया जाएगा और निरीक्षण के नोट बनाने की अनुमति होगी, किंतु किसी दस्तावेज की प्रतियां लेने की अनुमति नहीं होगी ।

23. कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय को शून्य घोषित किया जाना-(1) जहां आयुक्त द्वारा या अन्यथा किए गए अभ्यावेदन पर प्राधिकरण की जानकारी में यह लाया जाता है कि उसके द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय आवेदक द्वारा कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन से प्राप्त किया गया है वहां मामले की प्राधिकरण द्वारा परीक्षा की जाएगी और कोई भी अभ्यावेदन सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा और जिसके साथ निर्भर किए जाने वाले दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां लगी होंगी ।

(2) यदि अभ्यावेदन की परीक्षा करने के पश्चात् प्राधिकरण का प्रथम दृष्ट्या यह विचार है कि अग्रिम विनिर्णय आवेदक द्वारा कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन से प्राप्त किया गया प्रतीत होता है, आवेदक को यह स्पष्ट करने के लिए सूचना दी जाएगी कि, यथास्थिति, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28ट की उपधारा (1) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 23च की उपधारा (1) या सेवा कर उपबंधों की धारा 96च की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय को आरंभ से शून्य क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(3) आवेदक को ऐसी सूचना लिखित रूप में होगी-

(क) जिसमें उसे उन आधारों को सूचित किया जाएगा जिन पर अग्रिम विनिर्णय के आरंभ से शून्य घोषित करने की प्रस्थापना की जाती है ;

(ख) जिसमें उन दस्तावेजों यदि कोई हो, की प्रतियां संलग्न की जाएगी जिन पर निर्भर किया गया है ;

(ग) जिसमें ऐसे युक्ति युक्त समय के भीतर जो अग्रिम विनिर्णय को आरंभ से शून्य घोषित करने के लिए आधारों के विरुद्ध सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा ; और

(घ) जिसमें मामले में स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का उचित अवसर दिया जाएगा ।

(4) संलग्नकों के साथ सूचना की प्रति टीका-टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए आयुक्त को भी अग्रेषित की जाएगी और कोई आदेश पारित करने के पूर्व आयुक्त या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा ।

(5) जहां प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि अग्रिम विनिर्णय आवेदक द्वारा कपट या तथ्यों के दुर्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया था वहां उसे आरंभ से शून्य घोषित कर दिया जाएगा ।

24. कार्यवाहियों का जनता के लिए खुला होना- प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां जनता के लिए खुली होंगी और जहां आवेदक/आयुक्त ऐसा अनुरोध करता है, प्राधिकरण दिए गए मामले में यह आदेश कर सकेगा कि आवेदक, आयुक्त या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी कार्यवाहियों के दौरान उपस्थित नहीं रहेगा ।

25. आदेशों/अग्रिम विनिर्णयों का प्रकाशन- प्राधिकरण के ऐसे आदेशों/अग्रिम विनिर्णयों को, जिन्हें अध्यक्ष किसी प्रमाणिक रिपोर्ट या प्रेस में प्रकाशन के लिए उचित समझता है, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें अध्यक्ष विनिर्दिष्ट करे, ऐसे प्रकाशन के लिए जारी किया जाएगा ।

26. आदेशों/अग्रिम विनिर्णयों का अधिप्रमाणन और उनकी संसूचना-(1) प्राधिकरण का प्रत्येक आदेश/अग्रिम विनिर्णय, आदेश/अग्रिम विनिर्णय सुनाने वाले प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस पर प्राधिकरण की शासकीय मुद्रा लगी होगी ।

(2) प्राधिकरण के प्रत्येक आदेश/अग्रिम विनिर्णय की एक अनुप्रमाणित प्रति, आवेदक और आयुक्त को सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों से संसूचित की जाएगी और उस पर प्राधिकरण की शासकीय मुद्रा लगी होगी ।

27. प्राधिकरण की कार्यवाहियां- (1) जब अध्यक्ष से भिन्न प्राधिकरण के एक या दोनों सदस्य अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं अथवा सदस्यों के पदों में कोई रिक्ति या रिक्तियां होने की दशा में अकेला अध्यक्ष या अध्यक्ष और शेष सदस्य प्राधिकरण के रूप में कृत्य कर सकेंगे ।

(2) उस मामले में जहां किसी आवेदन पर सुनवाई करने वाले सदस्यों की राय में मतभेद हो, वहां उप विनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए सदस्यों के बहुमत की राय अभिभावी होगी और प्राधिकरण के आदेश/अग्रिम विनिर्णय सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे, किंतु बहुमत के विचार से विसम्मत होने वाला कोई सदस्य अपने कारण पृथक् रूप से लेखबद्ध कर सकेगा।

(3) जहां अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य उप विनियम (1) के अधीन किसी मामले की सुनवाई करते हैं और उनकी राय भिन्न-भिन्न है तो अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी।

28. अर्जी के मामले में प्रक्रिया- किसी आवेदन की सुनवाई और निपटान के लिए इन विनियमों में अन्तर्विष्ट उपबंध प्राधिकरण के समक्ष सभी अर्जियों की सुनवाई और निपटान को यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

29. पोशाक विनियम- (1) प्राधिकरण के समक्ष कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि ऐसी पोशाक में उपस्थित होगा, जो सक्षम वृत्तिक निकाय, यदि कोई हो, द्वारा उसकी वृत्ति के लिए सदस्यों के लिए विहित हो।

(2) प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले सभी अन्य व्यक्ति समुचित पोशाकों में होंगे।

30. आयुधों, मोबाईल फोन आदि का प्रतिषेध- कोई व्यक्ति, उस कक्ष में जहां प्राधिकरण कार्यवाही संचालित करता है, मोबाईल फोन, लाठी, आयुध या अन्य शस्त्र लाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. 16/02/2002]

विजय लक्ष्मी शर्मा, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
AUTHORITY FOR ADVANCE RULINGS
(CUSTOMS, CENTRAL EXCISE AND SERVICE TAX)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2005

No. 1/2005-AAR

G.S.R. 12(E).—In exercise of the powers conferred by section 28M of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), section 23H of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 96H of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) and in supersession of the Authority for Advance Rulings (Procedural) Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Authority for Advance Rulings (Customs, Central Excise and Service Tax) hereby makes the following regulations to regulate its own procedure in all matters arising out of the exercise of its powers under the said Acts, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Authority for Advance Rulings (Customs, Central Excise and Service Tax) Procedure Regulations, 2005 ["AARUL (CEST) Procedure Regulations"].

(2) They shall come into force on the 26th January, 2005.

2. Definitions.- In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) " advance ruling" means an advance ruling as defined in clause (b) of section 28E of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the Customs Act) or clause (b) of section 23A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Central Excise Act) or clause (a) of section 96A in Chapter VA of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (Chapters V and VA of the said Act referred to herein as the Service Tax Provisions), as the case may be;

(b) "applicant" means an applicant as defined in clause (c) of section 28E of the Customs Act or clause (c) of section 23A of the Central Excise Act or clause (b) of section 96A of the Service Tax Provisions, as the case may be;

(c) "application" means an application under sub-section (1) of section 28H of the Customs Act or sub-section (1) of section 23C of the Central Excise Act or sub-section (1) of section 96C of the Service Tax Provisions, as the case may be;

(d) "authorized representative",-

(i) in relation to an applicant means an authorized representative as defined in sub-section (2) of section 146A of the Customs Act or sub-section (2) of section 35Q of the Central Excise Act or referred to in sub-section (5) of section 96D of the Service Tax Provisions, as the case may be ;

(ii) In relation to a Commissioner, means a person –

(A) authorized in writing by the Commissioner to act as an authorized representative; or

(B) appointed by the Central Government as authorized representative or authorized by the Central Board of Excise and Customs to appear, plead and act for the Commissioner in any proceeding before the Authority;

(e) "Authority" means the Authority for Advance Rulings constituted under section 28F of the Customs Act and referred to in clause (e) of section 23A of the Central Excise Act and clause (d) of section 96A of the Service Tax Provisions;

(f) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;

(g) "Commissioner", in respect of an application, means -

(i) the Commissioner of Customs or the Commissioner of Central Excise, as the case may be, specified in the application; or

(ii) the Commissioner designated by the Chairman of the Central Board of Excise and Customs in respect of the application ;

(h) "Member" means a Member of the Authority and includes the Chairperson;

(i) "petition" means any petition of interlocutory, incidental or ancillary nature or representation filed in a pending or disposed of application;

(j) "Rules" means the Customs (Advance Rulings) Rules, 2002 or the Central Excise (Advance Rulings) Rules, 2002 or the Service Tax (Advance Rulings) Rules, 2003, as the case may be;

(k) "Secretary" means a Commissioner of Customs or Commissioner of Central Excise designated as Secretary by the Authority and includes an Additional Commissioner or a Joint Commissioner of Customs or of Central Excise, so designated;

(l) words and expressions used and not defined herein but defined in the Customs Act or the Central Excise Act or the Service Tax Provisions, as the case may be, shall have the meanings respectively assigned to them in that enactment.

3. Language of the Authority.- (1) The language of the Authority shall be Hindi/English.

(2) Where any document is in a language other than Hindi or English, a Hindi/English translation thereof duly attested shall be filed along with the original document.

4. Powers of the Authority. - (1) The Authority shall have the power to hear and determine all applications and petitions.

(2) The Authority may, if any difficulty arises in giving effect to its order/advance ruling, either *suo motu* or on a petition made by the applicant or the Commissioner within a period of three months of noticing the difficulty, by appropriate order remove such difficulty, and pass such other order as it considers just and necessary in the circumstances of the case.

(3) The Authority may reopen the hearing of any case, before pronouncement of its order/advance ruling, for sufficient cause.

(4) The Authority may, in an appropriate case, direct –

(i) examination of any records and submission of report;

(ii) conduct of any technical, scientific or market enquiry of any goods or services and submission of report and may also call for reports from experts and order such further investigation as may be necessary for effectual disposal of the application.

(5) The Authority shall have all the powers of a civil court in regard to the following matters, namely:-

(i) discovery and inspection ;

(ii) enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;

(iii) issuing commissions; and

(iv) compelling production of books of account and other records.

5. Powers and functions of the Secretary.—(1) The Secretary shall be in overall charge of the office of the Authority and shall function under direct supervision of the Chairperson.

(2) The Secretary shall –

(a) have custody of the records and the official seal of the Authority;

(b) receive all applications and petitions filed before the Authority;

(c) scrutinize applications and petitions and point out omissions and defects in the application/petition and require the applicant/petitioner to make good the omissions or remove the defects within the time granted by the Secretary and in case of non-compliance place such application/petition before the Authority for appropriate orders;

(d) forward a copy of the application alongwith its enclosures to the Commissioner to transmit records of the case, if any, and to offer his comments on the application;

(e) place all the applications before the Authority for appropriate orders under sub-section (2) of section 28I of the Customs Act or sub-section (2) of section 23D of the Central Excise Act or sub-section (2) of section 96D of the Service Tax Provisions, as the case may be;

(f) issue notices or other processes, as may be ordered by the Authority;

(g) verify service of notices or other processes on the parties to the application/petition and obtain necessary orders of the Chairperson in case of defective service;

(h) requisition records from the custody of any person, on the orders of the Authority;

(i) return original records to the person from whose custody they were requisitioned;

(j) allow inspection of the records of the Authority;

(k) carry out any amendment of the records of the Authority to conform to its directions ;

(l) grant to the parties to the application/petition certified copies of the orders/advance rulings and documents filed in the proceedings before the Authority;

(m) preserve records of every application / petition and other materials for a period of five years from the date of disposal of the application and to weed out/ destroy the same thereafter unless otherwise directed by the Authority ; and

(n) discharge any other function as may be assigned by the Authority by special or general order.

6. **Signing of notices, etc.** (1) Every requisition, direction, letter, authorization, or notice to be issued on behalf of the Authority, shall be signed by the Secretary or by any other officer authorized by him.

(2) Nothing contained in sub-regulation (1) shall apply to any direction which the Authority may issue to an applicant or a Commissioner or an authorized representative present during the course of the hearing.

7. **Mode of service of notices, etc.** - (1) The service of every notice or other document required to be served on or delivered to, any person in compliance with the orders of the Authority shall be in the manner specified hereunder.

(2) The service of notice or document shall be made by hand delivery or by registered post with acknowledgement due or by speed post or by courier service or by any other means of transmission of documents including e-mail/fax.

(3) Notices or documents required to be served on the parties to the application/petition shall be deemed to have been served, if delivered at the address indicated in the application/petition and in the case of a Commissioner at the Office of the Commissioner.

8. **Procedure for filing applications.** - (1) Every application filed before the Authority shall be in the prescribed form, that is to say, Form AAR (CUS) of the Customs (Advance Rulings) Rules, 2002 or Form – AAR (CE) of the Central Excise (Advance Rulings) Rules, 2002 or Form – AAR (ST) of the Service Tax (Advance Rulings) Rules, 2003, as the case may be.

(2) The application shall be filed in quadruplicate and presented by the applicant in person or by an authorized representative to the Secretary or any other officer authorized by the Secretary in this behalf or sent by registered post or by courier service or by speed post addressed to the Secretary along with a fee of two thousand five hundred Indian Rupees in the form of demand draft drawn in favour of "Authority for Advance Rulings (Customs, Central Excise and Service Tax)" payable at New Delhi.

(3) Applications for advance ruling shall be received between 10:00 a.m. and 1:00 p.m. and between 2:00 p.m. and 5:00 p.m. on any working day.

(4) Every application, its verification, annexures, statements and supporting documents shall be signed in the manner set out in the Rules.

(5) The application shall be accompanied by evidence that the person who has signed the application, verification and other documents is authorized/competent to sign under the Rules.

(6) Every application, its verification, annexures, statements and supporting documents shall be on A-4 size paper and should be neatly and legibly written, typed or printed leaving a left margin of 5 cms. and only on one side of a page in double-line spacing.

(7) An application under sub-regulation (1) shall be deemed to have been filed on the date on which it is received in the office of the Authority.

(8) If the applicant is not based in India, he shall, *inter alia*, indicate in a separate annexure to the application –

- (a) his postal and e-mail address abroad;
- (b) the name and address including e-mail address of his representative in India, if any, authorized to act on his behalf and to receive notices or other documents sent by the Authority.

9. Procedure on receipt of an application. – (1) The officer receiving the application shall put his initials and the stamp of the Authority thereon together with the date and time of receipt thereof and shall also acknowledge its receipt and he shall also enter the particulars of the application in the register of daily filing, maintained for that purpose.

(2) The application shall be scrutinized by the officer authorized by the Secretary for that purpose for any deficiency/defect and any deficiency/defect noticed in the application or annexures thereof shall be communicated to the applicant at the earliest.

(3) The applicant shall be required to rectify the deficiency/defect within the time granted by the Secretary and such application shall be deemed to have been received on the date when it is re-submitted after removal of such deficiency/defect, for the purposes of sub-section (6) of section 281 of the Customs Act or sub-section (6) of section 23D of

the Central Excise Act or sub-section (6) of section 96D of the Service Tax Provisions, as the case may be.

(4) Date of receipt of an application free from any defect or deficiency in the secretariat of the Authority shall be deemed to be the date of the application for the purposes of sub-section (4) of section 28H of the Customs Act or sub-section (4) of section 23C of the Central Excise Act or sub-section (4) of section 96C of the Service Tax Provisions.

(5) When an application is free from any defect/deficiency, an endorsement "examined and registered" shall be made thereon and a serial number allotted thereto.

(6) In case the defect/deficiency is not removed/made good within the time granted under sub-regulation (3), the application shall be placed before the Authority for appropriate orders.

(7) On allotment of serial number to an application under sub-regulation (5), a copy of the application shall be forwarded to the concerned Commissioner of Customs/Central Excise for furnishing relevant records with comments, if any.

(8) On receipt of the relevant records/comments from the concerned Commissioner under sub-regulation (7) or after expiry of two weeks or such further period as may be allowed by the Authority, the application shall be placed before the Authority for passing orders in terms of sub-section (2) of section 28I of the Customs Act or sub-section (2) of section 23D of the Central Excise Act or sub-section (2) of section 96D of the Service Tax Provisions, as the case may be.

(9) In a case where the Authority considers that *prima facie* the application is liable for rejection, a notice shall be issued to the applicant indicating the reasons therefor together with the comments, if any, of concerned Commissioner, giving an opportunity to the applicant of being heard in person or through an authorized representative and a copy of the notice shall be endorsed to the concerned Commissioner.

(10) On the date fixed for hearing or such other date to which the case is adjourned, the Authority may pass an order either allowing or rejecting the application under sub-section (2) of section 28I of the Customs Act or sub-section (2) of section 23D of the Central Excise Act

or sub-section (2) of section 96D of the Service Tax Provisions, as the case may be, and a copy of the order passed by the Authority shall be sent to the applicant and the concerned Commissioner.

(11) Where an application is allowed, the comments of the concerned Commissioner and further material, if any, shall accompany a copy of the order sent to the applicant drawing his attention to the statutory provisions that he has a right to be heard, if he so desires, before pronouncement of advance ruling and the response of the applicant should reach the Authority within two weeks of receipt of the copy of the order.

(12) Hearing of the application shall normally be held between 11:00 a.m. and 5:00 p.m. on a working day in the court-room of the Authority or an alternative place fixed by the Authority.

(13) In the absence of request for personal hearing from the applicant, advance ruling shall be pronounced after hearing the concerned Commissioner or his authorized representative, if present, on the date of hearing and on the basis of records available with the Authority.

(14) Where the Authority reserves an application for consideration, the advance ruling or such other order as the Authority may deem fit shall be pronounced in the open court under intimation to the applicant and the concerned Commissioner and a copy of the advance ruling/ order shall be served upon the parties to the application.

10. Commissioner to be designated by the Board.- Where in an application there is no Commissioner specified by the applicant, a copy of the application and enclosures thereto shall be forwarded by the Authority to the Chairman of the Central Board of Excise and Customs calling upon him to designate, within such period as may be fixed by the Authority, a Commissioner for the purposes of the application, failing which the application shall be proceeded with in the absence of a Commissioner.

11. Additional facts by way of a petition.- (1) The Authority may, at its discretion, either *suo motu* or on a petition made to this effect by a party to the application, permit or require the applicant or the Commissioner to submit such additional facts as may be necessary to enable it to pronounce its advance ruling.

(2) The additional facts sought to be brought on record, by the petitioner shall be supported by necessary documents, if any, duly verified.

12. Questions not specified in the application. - (1) The applicant shall not, except with the leave of the Authority, urge or be heard in respect of any question other than the question specified in the application but in pronouncing an advance ruling on the question set forth in the application, the Authority may at its discretion consider such other aspects as may be necessary to pronounce the advance ruling on the question specified in the application.

(2) On a petition made by an applicant, the Authority may permit amendment of a question, in appropriate cases.

13. Authorization to be filed.- (1) An authorized representative appearing for the applicant/Commissioner shall before the commencement of the hearing, file before the Secretary, a document authorizing him to appear for the applicant/Commissioner.

(2) Every authorized representative appearing on behalf of the applicant/Commissioner shall notify to the Secretary the address of his office, before the commencement of the hearing.

(3) Any change of an authorized representative shall be intimated by the concerned party to the Secretary as well as to the other party to the application.

(4) No person other than an applicant or the concerned Commissioner or their authorized representative, shall be heard in person save by special leave of the Authority.

14. Continuation of proceedings after the death, etc., of the applicant.- Where the applicant, being an individual, dies, or being a company or association of persons, whether incorporated or not, is wound up or dissolved or disrupted or amalgamated or succeeded to by any other person or otherwise comes to an end, the application shall not abate and the proceedings in the application may be continued by the executor, administrator, liquidator, receiver or assignee or other legal representative of the applicant, as the case may be, on a petition made in this behalf, if the Authority considers that the circumstances so justify.

15. Hearing of application.-(1) On the day fixed for hearing or any other day to which the case is adjourned, the Authority shall hear the applicant or his authorized representative in cases where it is proposed to reject the application or where the applicant seeks an opportunity of being heard; the Authority may also hear the Commissioner or his authorized representative, if it considers it necessary, before pronouncing its advance ruling.

(2) In an appropriate case, the Authority may call upon any person to depose or to supply such material/document, as it may consider necessary to arrive at a decision.

(3) The Authority may, in an appropriate case where an important question of law arises, issue notice to a Law Officer of the Central Government including the Attorney General and Solicitor General to assist the Authority in the matter.

(4) It will also be open to the Authority to appoint an advocate as *amicus curie* to assist the Authority in an application.

(5) The Authority may, on such conditions as the circumstances of the case require, adjourn the hearing of the application.

16. Hearing of application ex parte.- Where on the day fixed for hearing or any other day to which the case is adjourned, the applicant or the Commissioner does not appear in person or through an authorized representative when the application is called for hearing, the Authority may dispose of the application *ex parte* on merits:

Provided that where an application has been disposed of under this regulation and the applicant or the Commissioner, as the case may be, applies within seven days of receipt of a copy of the order/advance ruling and the Authority is satisfied that there was sufficient cause for his non-appearance when the application was called for hearing, the Authority may, after allowing the opposite party a reasonable opportunity of being heard, make an order setting aside the *ex parte* order/advance ruling and restore the application for fresh hearing.

17. Withdrawal of application.- The applicant may withdraw his application within thirty days from the date of such application and thereafter only with the leave of the Authority.

18. Modification of the order/advance ruling.- The Authority may *suo motu* or on a petition by the applicant or the Commissioner, but before pronouncement of an advance ruling or before an advance ruling pronounced has been given effect to, on being satisfied that an order/advance ruling was pronounced under mistake of law or fact, modify such order/advance ruling in such respects as it considers appropriate, after allowing the applicant and the Commissioner a reasonable opportunity of being heard.

19. Rectification of mistakes.(1) The Authority may, with a view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any advance ruling pronounced by it before such ruling has been given effect to.

(2) Such amendment may be made *suo motu* or when the mistake is brought to the notice of the Authority by the applicant or the Commissioner, but only after allowing the applicant and the Commissioner a reasonable opportunity of being heard.

20. Amendment of the records.- If at any stage of the proceedings it is brought to the notice of the Authority that there is any factual or material error in the records, the Authority may permit amendment of the records after hearing the applicant and the Commissioner.

21. Supply of certified copies.- The Secretary may grant certified copies of documents, orders or advance rulings to the applicant or the Commissioner on a written request.

22. Inspection of records.-(1) The applicant or the Commissioner or his authorized representative may be allowed to inspect the records of an application/petition on making a written request to the Secretary subject to the condition that only those documents shall be made available for inspection that are relied upon in the proceedings before the Authority.

(2) Inspection shall be allowed only in the presence of an officer of the Authority and taking of notes and not copies of the documents shall be permitted.

23. Declaration of advance ruling to be void in certain circumstances.- (1) Where it is brought to the notice of the Authority on a representation made by the Commissioner or otherwise that an advance ruling pronounced by it has been obtained by the applicant by fraud or misrepresentation of facts, the matter shall be examined by the Authority and any such representation shall be supported by an affidavit duly attested and accompanied with attested copies of documents relied upon.

(2) If the Authority after examining the representation is *prima facie* of the view that the advance ruling appears to have been obtained by the applicant by fraud or misrepresentation of facts, the applicant shall be given a notice to explain as to why the ruling should not be declared void *ab initio* under sub-section (1) of section 28K of the Customs Act or sub-section (1) of section 23F of the Central Excise Act or sub-section (1) of section 96F of the Service Tax Provisions, as the case may be.

(3) Such notice to the applicant shall be in writing –

(a) informing him of the grounds on which it is proposed to declare the advance ruling as void *ab initio*;

(b) enclosing copies of the documents, if any, sought to be relied upon;

(c) giving an opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice against the grounds for declaring the advance ruling void *ab initio*; and

(d) giving a reasonable opportunity of being heard in person or through an authorized representative in the matter.

(4) A copy of the notice with enclosures shall also be forwarded to the Commissioner for comments, if any, and a reasonable opportunity shall also be allowed to the Commissioner or his authorized representative of being heard before passing any order.

(5) Where the Authority finds that the advance ruling was obtained by the applicant by fraud or misrepresentation of facts, the same shall be declared void *ab initio*.

24. Proceedings open to the public.- Proceedings before the Authority shall be open to the public and where the applicant/ Commissioner so requests the Authority may order in a given case that

no person other than the applicant, the Commissioner or their authorized representatives shall remain present during such proceedings.

25. Publication of orders/advance rulings. - Such of the orders/advance rulings of the Authority, as the Chairperson deems fit for publication in any authoritative report or the press, may be released for such publication on such terms and conditions as the Chairperson may specify.

26. Authentication and communication of orders/advance rulings.- (1) Every order/advance ruling of the Authority shall be duly signed by the Chairperson and the Members of the Authority pronouncing the order/advance ruling and bear the official seal of the Authority.

(2) A certified copy each of order/advance ruling of the Authority shall be communicated to the applicant and the Commissioner under the signature of the Secretary or another officer of the Authority authorized by the Secretary in this behalf and bear the official seal of the Authority.

27. Proceedings of Authority- (1) When one or both of the Members of the Authority other than the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause or in the event of occurrence of any vacancy or vacancies in the office of the Members, the Chairperson alone or the Chairperson and the remaining Member may function as the Authority.

(2) Subject to the provisions of sub-regulation (3), in case there is difference of opinion among the Members hearing an application, the opinion of the majority of Members shall prevail and order/advance ruling of the Authority shall be expressed in terms of the view of the majority but any Member dissenting from the majority view may record his reasons separately.

(3) Where the Chairperson and one other Member hear a case under sub-regulation (1) and are divided in their opinion, the opinion of the Chairperson shall prevail.

28. Procedure in case of petition.- The provisions contained in these regulations for hearing and disposal of an application shall apply, *mutatis mutandis*, to the hearing and disposal of all petitions before the Authority.

29. Dress regulation.- (1) An authorized representative shall appear before the Authority in dress prescribed for the members of his profession by the competent professional body, if any.

(2) All other persons appearing before the Authority shall be properly dressed.

30. Prohibition of arms, mobile phones etc.—No person shall be allowed to bring mobile phones, sticks, arms or other weapons in the room where the Authority conducts the proceedings.

[F. No. 16/02/2002]

VIJAI LAKSHMI SHARMA, Commissioner